रॉ शुगर इंपोर्ट से साउथ की मिलों को होगा ज्यादा फायदा

[जयश्री भोसले | पुणे]

इस साल देश में 5 लाख टन कच्ची चीनी बाहर से आने वाली है। इसका सबसे ज्यादा फायदा पोर्ट पर बनी रिफाइनरीज के अलावा दक्षिण भारत की चीनी मिलों को होगा। इंडस्ट्री के मुताबिक, चीनी की ज्यादा किल्लत दक्षिण भारत में है, इसलिए सबसे बड़ा कोटा साउथ जोन को आवंटित होने से वहां की चीनी मिलों के फायदा होगा। कच्ची चीनी इंपोर्ट करने के लिए एप्लिकेशन जमा करने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल है।

इंपोर्ट के लिए सालभर चीनी की प्रोसेसिंग कर सकने वाली पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज के अलावा साउथ की चीनी मिलें एप्लिकेशन दे सकती हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) प्रेसिडेंट टी सरिता रेड्डी ने कहा, 'बहुत सी चीनी मिलों ने इंपोर्ट में दिलचस्पी दिखाई है।' यूपी में गन्ने की बंपर पैदावार होने के चलते उत्तर भारत में चीनी की सप्लाइ की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और साउथ के दूसरे राज्यों में चीनी का प्रॉडक्शन पिछले साल से कम रहा है। इसलिए 30 सितंबर को खत्म होने वाले शुगर ईयर 2016-17 के अंत में इस एरिया में चीनी की सप्लाई में कमी आ सकती है। इसलिए साउथ जोन को शुगर का ज्यादा इंपोर्ट कोटा देने के सरकारी फैसले से इस इलाके में चीनी की आपूर्ति की स्थिति बेहतर हो सकती है।

केंद्र सरकार ने 30 जून तक 5 लाख टन कच्ची चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दी है

केंद्र सरकार ने 30 जून तक 5 लाख टन कच्ची चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। इतनी कच्ची चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत महाराष्ट्र और कर्नाटक में शुगर प्रॉडक्शन में हुई कमी की भरपाई करने के मकसद से दी गई है। इसमें से 3 लाख टन का कोटा तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले साउथ जोन को मिला है। बाकी डेढ़ लाख टन वेस्ट जोन को दिया गया है जिनमें महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं जबकि बंगाल और उड़ीसा वाले ईस्ट जोन को 50 हजार टन इंपोर्ट की इजाजत दी गई है। रेड्डी कहते हैं, 'सरकार ने हालात का सही अंदाजा लगाया है और साउथ और वेस्ट की चीनी मिलों को बेनेफिट दिया है।'

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फेडरेशन के एमडी संजीव बाबर ने कहा, 'राज्य में पेराई सीजन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र की मिलें अब रॉ शुगर की प्रोसेसिंग करके सफेद वाली चीनी में बदल नहीं सकतीं।'

The Economic Times

21/4/17

Indian Sugar Mills Associat